cieties registered with the Registrar of Cooperative Societies, Delhi till August 1983 have been sponsored by him to the DDA for allotment of land. It has not been possible to consider them for allotment for want of land. Keeping in view the limited availability of land with the Delhi Development Authority and large backlog of registrants. It is difficult to indicate at this stage the extent to which it will be possible to accommodate the requirement of land to the registered co-operative group housing societies. However, it is proposed to give high priority to the allotment of land to societies registered under the 'Avas Sakar Yojana'.

फलों तथा सब्जियों की हानि का मूल्यांकन

2783. **श्री राम नरेश यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में फसल प्राप्ति से पहले उचित वसूली सुविधाओं की कमी की वजह से फलों और सब्जियों में भारी वार्षिक वित्तीय हानि आंकी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो फसल प्राप्ति के पहले और बाद में इन वस्तुओं में वार्षिक हानि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन हानियों को भरपाई करने के लिये विशेष प्रयास करने का निर्णय लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) से (ग) देश में फसल प्राप्ति से पहले खरीद की उचित सुविधाओं की कमी के कारण फलों तथा सब्जियों की हानि आंकने के संबंध में कोई सरकारी अनुमान नहीं है ।

सरकार ने ऐसी हानियों को कम करने के लिये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से निम्नलिखित योजनायें कार्यान्वित की हैं :--

(1) आलुओं के भण्डारण के लिये पैसिव इक्वेपोरेटिव कूल स्टोर बनाना ;

(2) फलों के रस/फलों पर आधारित पेयों के विपणन के लिये वैकल्पिक ढांचे तैयार करना ;

(3) फलों और सब्जियों के लिये बाजार आसूचना सेवाओं का राष्ट्रीय ग्रिड बनाना ; और

(4) बागवानी फसलों के फसल-कटाई के बाद के प्रबन्ध के पहलुओं के संबंध में राष्ट्रीय परियोजना ।

2784. [*Transferred to the 30th March, 1989*]

चीनी के मुक्त बिक्री राशन के कोटे में वृद्धि

2785. **श्री राम नरेश यादव :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चीनी मिल मालिकों के लाभ को बढ़ाने के लिये चीनी के मुक्त बिक्री कोटे के अनुपात को बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने कोटे के बढ़ाये जाने की संभावना है और कब तक ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष चीनी के उत्पादन मे वृद्धि के कारण पिछले वर्षों की अपेक्षा मिलों के लाभों में वृद्धि होने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार के निर्णय और इस वर्ष अधिक उत्पादन के कारण लाभ के अनुपात के किस सीमा तक बढ़ने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा): (क) और (ख) सरकार ने दिसम्बर 1988 में पहले ही इस आशय की घोषणा कर दी है कि सार्वजनिक वितरण